

भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे जाएंगे : पीएम

पीएम मोदी ने रामायण देखी, कहा-इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा

बैंकॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की।

उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियां थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।

इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की।

इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यहां रामायण को रामाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा (38) से द्विपक्षीय मुलाकात की। वे दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने कहा कि पीएम शिनवात्रा ने मुझे त्रिपिटक भेंट किया। ‘बुद्ध भूमि’ भारत की ओर से, मैंने इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। पिछले साल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से थाईलैंड भेजे गए थे। मैं यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि गुजरात के अरावली में 1960 में मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भी थाईलैंड भेजे जाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो



पैसिफिक विजन में थाईलैंड का खास योगदान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का रूप देने का फैसला किया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटजिक डायलॉग स्थापित करने पर चर्चा की गई।

साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए थाईलैंड सरकार का शुक्रिया। हमारी एजेंसी ह्यूमन ट्रेनिंगिंग और अवैध माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों और

थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एएमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। रिन्युएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई-व्हीकल्स, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्ट अप में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दोनों देशों के बीच फिन्नेटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम किया जाएगा। भारत ने थाई पर्यटकों के लिए ई-वीजा देना शुरू कर दिया है।

थाईलैंड के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जा सकते हैं पीएम मोदी गुरुवार को पीएम मोदी थाईलैंड के ऐतिहासिक वात फो मंदिर भी जा सकते हैं। वात फो मंदिर बैंकॉक

में स्थित है और अपने विशाल लेटे बुद्ध (रिक्लाइनिंग बुद्ध) प्रतिमा के लिए फेमस है। वात फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसमें 1,000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से अधिक स्तूप हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बिस्मटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के बाद वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। युनुस के मुख्य सलाहकार खलौलुर रहमान ने बुधवार को इसकी संभावना जताई है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। 2024 में थाकसिन शिनवात्रा की बेटे पाइतोंगतान शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बर्नी। अक्टूबर 2024 में वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मोदी से पहली मुलाकात हुई थी।

उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण पर केंद्रित वर्कशाप और मेले जिला स्तर पर लगाए : डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की जिलेवार मैपिंग की जाए। विश्वविद्यालय सहित अन्य शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित करने तथा प्रदेश में पीपीपी मोड पर नर्सरीयां विकसित करने के लिए कार्य योजना बनायी जाए। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण पर केंद्रित वर्कशॉप और मेले आयोजित कर जिलों के किसानों और उद्यमियों को अन्य जिलों में संचालित बेस्ट प्रैक्टिसेज से परिचित कराया जाए। जिलों में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करने तथा अपने स्तर पर इस क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले किसानों का सम्मान किया जाए। इन्वेस्टर्स समिट के समान प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर समिट का आयोजन हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण विभाग की समीक्षा के



दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषि विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से सम्पन्न है, साथ ही सिंचाई और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश कि उद्यानिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकले। उद्यानिकी के साथ खाद्य प्र-संस्करण के माध्यम से

रोजगार के अवसर निर्मित करने की दिशा में भी अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जाए। विभाग में विशेषज्ञों तथा तकनीकी दक्षता पर केंद्रित सेल स्थापित कर खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के तीनों क्षेत्रों चंबल-मालवा और महाकौशल में उद्यानिकी की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत और उपज का वाजिब मूल्य मिले, उन्हें यह भरोसा दिलाना आवश्यक है।

चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिश्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा- हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी



है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई।

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बीती 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेंडेंहोंग के साथ काटा था। फेंडेंहोंग ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की थीं।

राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने कहा- एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया। इससे देश की ऑटो, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राहुल ने कहा- एक बार किसी ने ईंदिरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया की मैं बाएं या दाएं नहीं झुकती। मैं भारतीय हूँ और सीधी खड़ी हूँ।

जिस वक्फ पर विवाद नहीं, उस पर कानून प्रभावी नहीं : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूँ। इस दौरान सरकार ने एक और बात स्पष्ट की। वह थी कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद कैसे मामलों में दखल दिया जा सकता है। सरकार ने साफ किया कि कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, मंत्री ने कहा कि यह उसी स्थिति में है, जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है।

वक्फ बिल जबरन पारित कराया गया : सोनिया

सोनिया गांधी ने विधेयक को लेकर की गई जल्दबाजी के लिए सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विधेयक और उसे पारित कराने के लिए सरकार की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जबरन पास कराया गया है, इसे धोपा गया है।

कांग्रेस संसदीय पार्टी की आम सभा की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पारित हो गया और आज इसे



राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस

संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है। सरकार शिक्षा, नागरिक अधिकार, लोगों की स्वतंत्रता, हमारे संघीय ढांचे, या चुनाव का संचालन हो, किसी को भी बख्शा नहीं रही है। उन्होंने दावा किया कि अब हमारा संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। हम जानते हैं कि उनका इरादा उसे भी ध्वस्त करने का है। बैठक में सांसदों से सोनिया ने कहा, हम सभी के लिए यह जरूरी है कि हम सही और न्याय के लिए लड़ते रहें।

वक्फ बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरुआत है : संजय



नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार रात करीब एक बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288, जबकि विरोध में 232 मत पड़े। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया। विपक्षी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर रात सवा बजे मतदान हुआ, जो

231 के मुकाबले 288 से खारिज हो गया। इसमें बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य न रखने का प्रस्ताव था। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। अब विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर क़नेता संजय सिंह ने कहा, हमने इस बिल का जेपीसी में भी विरोध किया, कल लोकसभा में भी विरोध दर्ज करवाया और आज जब यह बिल राज्यसभा में आया तो यहां पर विरोध करेंगे।

अमेरिका ने भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया

ट्रम्प बोले- मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं, बदलाव 9 अप्रैल से लागू होगा

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ (रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ) लगाने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा- भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ



वसूल रहे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे। इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। भारत के अलावा चीन पर 34%,

यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ को तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन (न्यूनतम) टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे।

बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा। अब तक अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता था। जबकि भारत 60%, वियतनाम 70% और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं।

सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

पुलिस ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को हिरासत में लिया

बंगलूरु। बंगलूरु में गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोला। भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और भाजपा नेता सीटी रवि समेत कई कार्यकर्ताओं को

को हिरासत में लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक सरकार ने डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। इसे लेकर भाजपा विरोध कर रही है। बुधवार को भाजपा ने फोर्डम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा, जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम लोग संघर्ष कर रहे हैं।

संसद में पारस्परिक टैरिफ का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस: खरगे

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26 फीसदी पारस्परिक टैरिफ ने एक राजनीतिक मुद्दे को जन्म दे दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ट्रंप एक व्वबसायी हैं, और हमारा ग्राहक फंस गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बृहस्पतिवार को संसद के बाहर कहा कि उनकी पार्टी अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर चर्चा करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति

जजों की बैठक में लिया गया अहम फैसला



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत में हुई न्यायाधीशों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित 30 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्तियों को न्यायाधीशों की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से प्रकट करने पर सहमति व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक एक अप्रैल को हुई बैठक

में जजों ने संकल्प लिया कि न्यायाधीश जब भी पदभार ग्रहण करेंगे या कोई अहम जिम्मेदारी लेंगे तो उनकी मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अब तक 1997 के एक प्रस्ताव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी होती थी। 2009 के एक निर्णय में न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति घोषणा के स्वैच्छिक प्रकाशन की न्यायाधीशों ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सामूहिक रूप से संपत्ति के खुलासे को सार्वजनिक करने पर सहमति जताई।

भू माफिया बन गया वक्फ बोर्ड, यूपी में माफियागीरी नहीं चलेगी : योगी

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 579 करोड़ रुपये की 181 परियोजनाओं की सौगत दी। इसके पूर्व उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कर निषादराज और भगवान राम के मिलन की पावन धरती को प्रणाम किया। सीएम ने निषाद राज उद्यान में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा राजा निषाद व श्रीराम से जुड़ी कथाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत प्रशिक्षित समूह की महिलाओं द्वारा मूंज से उत्पादों ओडीओपी की प्रदर्शनी को भी



देखा। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड का काम नमामा दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप यहां निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह-जगह वक्फ के नाम पर

कब्जे किए गए हैं। यहां तक की कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था- क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है।

निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्यवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की।

योगी ने कहा कि ‘हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगातार लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और

अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया और बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि ‘जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 ने देश-प्रदेश को बहुत कुछ दिया। इतना बड़ा आयोजन समानतन धर्मावलंबी और राम भक्त ही कर सकते हैं। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वे ही इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते।



रात मे रेत तो दिन मे हेरोइन का धंधा पकड़ा जोर

ट्रेक्टर की धमा चौकड़ी से परेशान आम जनता, एक अधिकारी लूटवा रहे अपनी वाहवाही

सिंगरौली। देशभक्ति और जनसेवा की कसम खाने वाली कोतवाली पुलिस के नाक के नीचे रात भर रेत और मिट्टी का कारोबार जबकि दिन में गांजा और हीरोइन का धंधा जोरों से चल रहा है। खनिज संपदा के दोहन से जहां सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है तो वही नशे के जाल में नई पीढ़ी फसती जा रही है। इस कारोबार में पुलिस की कमाई पहले के मुकाबले अधिक होने की चर्चाएं हो रही हैं।

सूत्रो की बातों पर गौर करे तो कोतवाली क्षेत्र लंबे समय से कोयला, कबाड़, डीजल, अवैध रेत, गांजा, शराब को लेकर सुर्खियों में रहा है। चर्चा है कि अवैध कारोबार पुलिस के मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के निगरानी में जोर पकड़ रहा है। लेकिन हेरोइन की बिक्री से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दुख और पीड़ा की बात है कि कालेज के बच्चों और युवा नशे की चपेट में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, नशे की बुराई के खिलाफ अभियान चलाने वाले जिम्मेदार आंकड़ों की बाजीगरी में आगे हैं। आंकड़े जरूर बताते हैं कि शहर में अवैध खनिज

संपदा और नशा के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन हालात इसके ठीक विपरीत है। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर गांजा और हेरोइन आसानी से मिल जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि गस्त का दम भरने वाली पुलिस और क्षेत्र में नजर रखने वाले बीट प्रभारी आखिर कर क्या रहे। सुत्रों का दावा है कि सभी बीट प्रभारी अवैध कारोबारियों से हर महीने सुविधा शुल्क लेकर उन्हें अवैध काम करने की छूट दे रखी है। इधर बता दे कि जब नए पुलिस कप्तान सिंगरौली आए तो किसी से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनते और शेखी बघारते हर कोई सुना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रृंगी ऋषि की धरती में ऐसा क्या हुआ की साहब का सारा तजुर्बा फेल हो गया। क्या साहब ने अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं किया या फिर उनके मातहत कर्मचारी कामों में जो समर्पण दिखाना चाहिए था उसमें कहीं चूक हुई। कमी जहां भी रही हो लेकिन जिले के बर्धौरा चौकी क्षेत्र में आगजनी की घटना और कोतवाली अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड में अचानक दो बसों का धू-धू कर

जलना पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे।

नगर और ग्राम रक्षा समिति पर भी लग रहे आरोप

पुलिस हर जगह नहीं मौजूद रह सकती, अपने सूचना तंत्र को बढ़ाने पुलिस ने नगर और ग्राम रक्षक समिति बनाई। यह पुलिस की तीसरी आंख मानी जाती है। समिति के सदस्य पुलिस के सहयोगी बनकर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। बावजूद इसके शहर और गांवों में धड़ल्ले से अवैध शराब और गांजा की बिक्री की जा रही है। सुत्रों का दावा है कि नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य भी अवैध कारोबार में बराबर सहभागी है। यह तो कहते हैं कि जब वक खराब हो तो ऊंट में बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता भी काट लेता है लेकिन इसके उलट यह भी है कि जब वक सही हो तो हर कोई बच्कर शेर बन जाता है लेकिन कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि की धरती पर बड़े-बड़े बच्कर शेरों को लोग पस्त होते भी देखा है। यह शनि और राहु का प्रकोप है या अधिकारियों का अधिक आत्मविश्वास। यह तो कोई राजनीतिक विश्लेषक या फिर

प्रख्यात पंडित ही बता सकता है। यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जिले में एक ऐसे ही अधिकारी की चर्चा है कि जो छिंदवाड़ा में अपने कार्यकाल को उपलब्धियों के तौर पर गिनाते रहे हैं, लेकिन जब से जिले में आमद दिए हैं कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।

कोतवाली क्षेत्र में दो नंबरियों का बोलबाला

सूत्र बताते हैं कि कोतवाली क्षेत्र हमेशा से ना केवल रेत मिट्टी के अवैध कारोबार के लिए बल्कि कोयला, कबाड़, शराब, गांजा हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के लिए बदनाम रहा है। यहां धधकते ईंट भट्टे पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए चुनौती रहे हैं। हालांकि इन दो नंबरियों को पुलिस के सिपाही से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक ने अपने जरूरत के मुताबिक पोषित किया। क्योंकि पुलिस की कमाई अवैध कामों पर ही टिकी है। सुत्रों का दावा है कि रेत, मिट्टी, मुरुम, कोयला और राखड़ वाहनों से कोतवाली पुलिस करीब 20 लाख रुपए महीना वसूल रही है।

नवांकुर संस्था ने बरदघटा में रैली निकालकर जल संरक्षण के लिए किया प्रेरित



सिंगरौली। जिले मे भर में 30 मार्च से लगातार वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान चालाया जा रहा है अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई उनका गहरीकरण , जीर्णोद्धार करने के साथ ही जागरूकता रैली निकालकर आम लोगों को जल संरक्षण के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज म.प्र.जन अभियान परिषद् नवांकुर संस्था द्वारा ग्राम पंचायत बदरघटा में रैली निकालकर ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही जन सहयोग के माध्यम से ग्राम में स्थित खेत तालाब की साफ सफाई कर ग्रामीणों को जन सहयोग से जल स्रोतों के संरक्षण, रखरखाव करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राजकुमार विश्वकर्मा सहित नवाकुर संस्था के सदस्य एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

पार्टी का स्थापना दिवस भव्य उत्सव की तरह मनाया जाएगा : प्रज्ञा त्रिपाठी

भाजपा की विशेष बैठक में बोलीं संगठन प्रभारी

सिंगरौली। भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली जिले की संगठन प्रभारी श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचीं। संगठन प्रभारी के मुख्य आतिथ्य में जिला कार्यालय पर एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ जिसको अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने की। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, पूर्व विधायक राम लालू वैश्य, सुभाष वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी, राम सुमिरन गुप्ता, वीरेंद्र गोयल, सीडा अध्यक्ष दिलीप शाह निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय, मंचासीन रहे।

जिला मीडिया प्रभारी नीरज सिंह परिहार ने बताया कि कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ भारत माता तथा पितृ पुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। बैठक में स्वागत उद्बोधन जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने दिया जिसमें उन्होंने पथारे समस्त अतिथियों, पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष ने आयोजित बैठक की भूमिका प्रस्तुत की तथा आने वाले कार्यक्रमों जिसमें 6 अप्रैल पार्टी के स्थापना दिवस, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ग्राम चलो अभियान



एवं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के बारे में चर्चा की। विधायक रामनिवास शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम अपने सांगठनिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र की जनता के बीच जाते रहते हैं इस अवसर का उपयोग हमें सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी एवं उनको जनता के बीच पहुंचाने के लिए करना चाहिए। इससे हमारी सरकार का जनकल्याण का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। अपने उद्बोधन में संगठन प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से कहा? कि 6 अप्रैल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को हमें एक भव्य उत्सव की भांति मनाना है। हमें अपने घर और आस पड़ोस से लेकर समाज के हर वर्ग के बीच स्थापना दिवस का उत्सव मनाना है। कार्यालय में संगठन की यात्रा संबंधित प्रदर्शन लगाना है। इसके अतिरिक्त 6 एवं 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर प्राथमिक

सदस्यों के साथ कार्यक्रम करने हैं 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल अथवा विधानसभा स्तर पर समस्त सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करना है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजकुमार दुबे ने की तथा आभार प्रकट जिला महामंत्री लालपति साकेत ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष देवसर प्रणव पाठक, नगर परिषद अध्यक्ष प्रमिला देवी, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल चतुर्वेदी, अरविंद दुबे, सरोज शाह, आशा यादव, सरोज सिंह, जिलामंत्री ध्रुव सिंह, प्रवेन्द्र धर द्विवेदी, अरविंद तिवारी, विनोद चौबे, पुनम गुप्ता, आर्यालय मंत्री कृष्ण कुमार कुशवाहा, समस्त वर्तमान मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष, मोर्चा जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल, राजेंद्र सिंह, दिल शरण सिंह, कमलेश वैश्य, वरिष्ठ नेताओं में नरेश शाह, अरुण देव पांडेय सम्मिलित रहे।

सवा साल बाद भी नही हटा अतिक्रमण, बरहट गांव का मामला

तहसीलदार चितरंगी ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को बेदखली का जारी किया था नोटिस

सिंगरौली। स्थानीय तहसील क्षेत्र के ग्राम बरहट में एक भूमि स्वामी के भूमि पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा है। तहसीलदार चितरंगी ने इन कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली नोटिस जारी किया था। जहां सवा साल बाद भी पट्टेदार की भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाई है।

ग्राम मनिकपुर निवासी मंगला प्रसाद द्विवेदी पिता अंजनी कुमार द्विवेदी के ग्राम बरहट स्थित पट्टे की आराजी में सतई पिता नाहक, गुड्डू पिता अजोरे हरिजन, हितलाल जायसवाल, इन्द्रमणि

साहू समेत आधा दर्जन लोगों ने खसरा क्रमांक 1404 रकवा 0.60 हेक्टेयर रकवा में कब्जा कर रखा है। इनके खिलाफ तहसील से 31 मार्च 2021 को अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुये तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया था। जहां अनावेदकों ने उपखण्ड अधिकारी चितरंगी के यहां अपील किया, लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने उक्त आवेदन पर को अस्वीकार कर दिया था और 31 मार्च 2021 के तहसीलदार के आदेश को स्थिर माना गया। वही 16 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार

चितरंगी ने उक्त अतिक्रमण कार्रियों को बेदखली नोटिस जारी कर तीन दिवस के अन्दर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और निर्देश दिया गया था कि स्वयं अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को अवगत करायेगे। लेकिन तहसीलदार आदेश के करीब साढ़े पाँच सौ दिन के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आवेदक ने इस ओर कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार चितरंगी का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त आराजी को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की मांग की है।

मार्च महीने मे यातायात पुलिस ने 1723 लापरवाह वाहन चालको पर की कार्यवाही

सिंगरौली। थाना यातायात द्वारा माह मार्च में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1723 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध की गई चलानी कार्यवाही करते हुए बारह लाख चौबीस हजार रूपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किए जाने के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात प्रभारी दीपेन्द्र सिंह की टीम के द्वारा शहर के चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 1 मार्च से 31 मार्च 2025 तक 1723 से

बारह लाख चौबीस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर किया जागरूक

अधिक वाहनों पर कार्यवाही की गई। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम लगाया जाकर शहर के विभिन्न चौराहे जैसे माजन मोड़, इंदिरा चौक, अंबेडकर चौक, मस्जिद तिराहा, कालेज तिराहा ,अमलोरी तिराहा, जयंत बस पड़ाव, निम्न स्थानों पर यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना,दो पहिया



वाहन पर तीन सवारी बैठ कर वाहन चलाना,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ,वाहनों का नम्बर प्लेट निर्धारित मानक अनुरूप ना होना,शराब पीकर वाहन चलाना ,दो पहिया वाहनों या बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन साइलेंसर

लगाना,शहर के अंदर निर्धारित गति का पालन न करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाना,रेड लाइट जम्प करना व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करना के साथ नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही के साथ-साथ समझाइए भी दी गई साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी गई । वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा बांडीवार्म कैमरे की निगरानी में चलानी कार्यवाही की जा रही है बांडीवार्म कैमरे के

माध्यम से चालानी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। नो पार्किंग एवं सड़क पर खड़े वाहनों पर व्हील लॉक लगाकर कार्यवाही की जा रही है। शहर की सड़कों पर नो पार्किंग जोन में वाहन चालकों द्वारा वाहनों को खड़ा कर यातायात अवरोध किया जाता है ऐसे वाहनों पर भी व्हील लॉक लगाकर चालानी कार्रवाई यातायात पुलिस टीम के द्वारा माजन मोड़ से इंदिरा चौक तक मुख्य मार्ग में की जा रही है एवं स्थाई रूप से खड़े वाहनों को लगातार हटवाया जा रहा है।

सरई तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे कोनी विद्यालय

सामान्य ज्ञान के माध्यम से बच्चों की बौद्धिक क्षमता को निखारने का किया प्रयास

सिंगरौली। सिंगरौली जिले के सरई तहसील अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के कोनी मे स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को एक प्रेरणादायक दृश्य उस समय देखने को मिला सरई तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा और थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने शिक्षक की भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति मात्र ने विद्यालय के वातावरण में नई ऊर्जा का संचार कर दिया, और बच्चों के चेहरों पर उल्लस साफ झलक रहा था। कलेक्टर सिंगरौली

के निर्देशानुसार शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक अधिकारियों को विद्यालयों तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में तहसीलदार और थाना प्रभारी ने विद्यालय में न केवल उपस्थिति दर्ज की बल्कि स्वयं शिक्षण कार्य में भी भाग लिया। विद्यालय के कक्षाओं में जाकर दोनों अधिकारियों ने बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं



पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया। तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा ने सामान्य ज्ञान के माध्यम से बच्चों की बौद्धिक क्षमता को निखारने का प्रयास किया। उन्होंने सरलता और रोचकता के साथ अध्यापन कर

बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने नैतिक शिक्षा और अनुशासन के महत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बच्चों को ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने की शिक्षा दी। उनकी प्रेरणादायक बातें बच्चों के मन-मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ गई। ज्ञान-विज्ञान की परिचर्चा के माध्यम से अधिकारियों ने बच्चों को उनके जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने

हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि सफलता के मार्ग पर चलने के लिए आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। यह पहल निश्चित ही शिक्षा के प्रति समर्पण और जागरूकता का अनुपम उदाहरण है। बच्चों के बीच अधिकारियों की उपस्थिति ने उनमें आत्मविश्वास का संचार किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि समाज के वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत हैं।

जल संरक्षण के छोटे-छोटे प्रयास जल संकट को दूर करने में होंगे सहायक : राज्यमंत्री

सिंगरौली। प्रदेश के साथ साथ सिंगरौली जिलें मे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंशानुसार 30 मार्च से लेकर 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा हैं। अभियान के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे स्थित जल संरचनाओं स्रोतो के संरक्षण एवं पुर्नजीवन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान से जन समुदाय को जोड़कर जल संरक्षण एवं जल के जीवन में महत्व के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम



में विगत दिवस ग्राम पंचायत खम्हरिया में जलगंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम का आयोजन राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह मंत्री मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अतिथि एवं सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह, कलेक्टर

चन्द्र शेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के गरिमामय उपस्थित में कर ग्रामीणों को जल संरचनाओं के संरक्षण एवं जीवन में जल के महत्व को विस्तार से अवगत कराने के साथ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को जल संरचनाओं की महत्वता के बारे में बताते हुये राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

हिंदू परिषद बजरंग दल ने एसपी को सौपा ज्ञापन

सिंगरौली। 1 अप्रैल 2025 को जॉय स्कूल विजय नगर के संचालक अखिलेश मैबन के द्वारा भगवान श्रीराम जी के लिए एवं समस्त हिन्दू समाज के विरुद्ध अपमान एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इन्हीं के ईसाई समुदाय से आने वाले लोगों ने इसको शेयर किया। जिसके विरोध मे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एसपी को ज्ञापन सौपा है।



ज्ञापन मे बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक स्थलों में प्रदर्शन किया जा रहा था। वहाँ पर भी इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को उकसाने एवं अपशब्दों का प्रयोग स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया जाने लगा जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो पुलिस

तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं अखिलेश का जो घर बना हुआ है यह भी अवैध रूप से बनाया गया है इस पर बड़ी से बदी कार्रवाई की जाए इसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए एवं इसके साथ में डेविड जॉर्ज अरविंद, एंड्रयू, क्रिस्टोफर एंथोनी, इसाक चौरै (बाँबी) एवं अन्य लोगों ने प्रभू रामजी के खिलाफ में की गई टिप्पणी को शेयर किया ये वो अपने फेसबुक से डाला है उन सभी की जाँच पड़ताल करके उन सभी के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भविष्य में उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

सिंगरौली में कचरा घोटाला ? हर महीने करोड़ का हो रहा खेल

सिंगरौली। ऊर्जाधानी को यूं ही अजब है, सबसे गजब है नहीं कहा जाता. यहां के घोटाले भी अजीबोगरीब होते हैं. हाल ही में चम्मच घोटाला और स्टोर घोटाला चर्चा में थे और अब सिंगरौली नगर निगम का कचरा परिवहन घोटाला होने की चर्चाएं तेज हो गई है. शहर में खुली पड़े प्लांटों पर फैला कचरा और नालियों में जमा कचरे का गोंद अपनी दास्तान चीख चीख कर बयां कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार कागजों पर स्वच्छता अभियान चलाकर पैसों की बंदर बाट कर रहे हैं। वहीं पूर्व कमिश्नर और स्वच्छता नोडल अधिकारी ने सरकार को खुले में शौच मुक्त की झूठी जानकारी दे दी। साथ ही ओडीएफ का सर्टिफिकेट लेकर वाह-वाही लूट रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने



सरकार को झूठी जानकारी देखकर ओडीएफ प्लस का तमगा भले हासिल कर लिया है लेकिन आज भी ऐसे हजारों घर हैं जहां शौचालय बना ही नहीं। आज भी बच्चों से लेकर महिलाएं तक खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अधिकारी बेशर्मी से दांत निपोरते हुए कहते हैं कि शहर खुलें में शौच से मुक्त हैं। कमोवेश हालात स्वच्छता अभियान का भी है। पूरा शहर गंदगी के ढेर पर खड़ा हैं। नालियां कचरा से

बजबजा रही है। कागजों पर स्वच्छता अभियान चल रहा है, हर महीने दो करोड़ के करीब नगर निगम स्वच्छता पर खर्च कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत ओडीएफ झूठ जितना ही नजर आ रहा है। पार्षद भी घर-घर कचरा संग्रहण में लगी कम गाड़ियों को लेकर सिटाडेल कंपनी और नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगाए हैं। पार्षदों ने घर-घर कचरा संग्रहण में लगी गाड़ियों की संख्यात्मक जानकारी

भी मांगी लेकिन जिम्मेदार हर बार सवालों को जोड़-तोड़ कर भ्रामक जानकारी देकर सिटाडेल कंपनी के प्रति अपनी ईमानदारी और वफादारी का सबूत जरूर दिया। नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड आते हैं। जहां करीब आधा दर्जन वार्डों में आज भी हजारों घर में शौचालय नहीं बने हैं। अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए हर घर में बिना शौचालय बनाए ही सरकार को झूठी जानकारी सबमिट कर दी। साथ ही भोपाल और दिल्ली जाकर मंडल लिए। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि यहां हजारों मकान ऐसे हैं जहां शौचालय बना ही नहीं। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, हर दिन शर्मसार हो रही हैं। पार्षदों का आरोप है कि सभी

ठेकेदारों की फाइल बिना भौतिक परीक्षण और चढ़ोतराी के अधिकारी दस्तखत नहीं करते हैं लेकिन सिटाडेल कंपनी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनी के बिल भुगतान की फाइल जिस टेबल पर पहुंचती है, अधिकारी बिना समय गंवाए दस्तखत कर भुगतान कर देते हैं। सुत्रों का दावा है कि सिटाडेल कंपनी में भोपाल स्तर के एक बड़े नेता का शेयर हैं। लिहाजा अधिकारी भी सिटाडेल कंपनी के बिल भुगतान को रोकने की हिमाकत नहीं कर पा रहे। चर्चा हैं कि एक अधिकारी ने भुगतान पर ऑब्जेक्शन किया था तो उसे भोपाल से फोन आ गया था। उसके बाद से किसी अधिकारी ने भुगतान रोकने का साहस नहीं जुटा पाया।



‘वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे’ पर अभिभावकों को किया गया जागरूक

सीधी। सीधी जिला चिकित्सालय के जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र और दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र में ‘वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे’ के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष भारती और डॉ. विनय सिंह, डीईआईसी सीधी के मैनेजर पुष्पेंद्र शुक्ला तथा डीडीआरसी सीधी के विशेष शिक्षक शिवांसु शुक्ला ने भाग लिया और अभिभावकों को जागरूक किया।

विशेषज्ञों ने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है, जो अधिक स्क्रीन टाइम के कारण विशेष रूप से दो साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। जब छोटे बच्चे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताने लगते हैं, तो उनके व्यवहार और संचार कौशल पर नकारात्मक प्रभाव

पड़ता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और माता-पिता के बुलाने पर प्रतिक्रिया न देना। खेल-कूद में रुचि की कमी और खिलौनों से खेलने का तरीका न समझ पाना। सामाजिक मेल-जोल में कमी, यानी दूसरों से घुलने-मिलने में रुचि न लेना।

मूड स्विंग, जिद्दीपन और चिड़चिड़ापन। याददाश्त और समझने की क्षमता पर असर।

डॉ. आशीष भारती, डॉ. विनय सिंह, पुष्पेंद्र शुक्ला और शिवांसु शुक्ला ने अभिभावकों को इस समस्या से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दो साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गोपाल दास तालाब की साफ-सफाई की गई



सीधी। जिला समन्वयक जन अभियान परिषद शिवदत्त उर्मलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज के नेतृत्व में पूरे जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन सहभागिता को लेकर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा जल

गेहूँ उपार्जन के लिये किसान अब 9 अप्रैल तक करा सकते हैं पंजीयन

सीधी। जिला आपूर्ति अधिकारी नागेंद्र सिंह परिहार ने जानकारी देकर बताया कि किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन जरूर करावें। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनास दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।

छात्रों के हितों के दृष्टिगत आवश्यक है विश्वविद्यालय : सांसद

लोकसभा में सांसद डॉ राजेश मिश्र ने उठाया सीधी मुख्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना का मुद्दा

सीधी। गुरुवार को लोकसभा में सांसद डॉ राजेश मिश्र ने सीधी में विश्वविद्यालय की मांग रखते हुए कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन जिले सीधी, सिंगरौली का पूरा भाग व शहडोल जिले का आधा भाग आता है, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

लोकसभा सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि सीधी व सिंगरौली जिला दूरचल एवं

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि सीधी जिला मुख्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना कि जाती है तो उक्त छात्र- छात्राओं को सुविधा तो होगी ही साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम भी स्थापित होंगे शत प्रतिशत बालक बालिका साक्षर होंगे। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि जिला मुख्यालय सीधी में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। ज्ञात हो कि सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न मुद्दे उठा चुके हैं, लगातार मंत्रीगण और अधिकारियों से मिलकर भी उन्होंने विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान सांसद ने बताया कि सीधी संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही मेरा लक्ष्य है, मैं रूपरेखा बनाकर संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु प्रण के साथ जुटा हूँ।

भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन के लिए दल गठित

सीधी। संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग भोपाल के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों हेतु विकासखण्ड का जिले में क्रियान्वयन दिनांक 02 अप्रैल 2025 से 08 अप्रैल 2025 के मध्य किया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर प्रतियोगिता के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित अवधि में योजना का क्रियान्वयन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर खंड पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों का दल गठित किया गया है।

जारी आदेशानुसार जिला स्तरीय गठित दल में डॉ वीरेन्द्र विक्रम सिंह ख.प.चि. अधिकारी, डॉ अनामिका पांडे प.चि.स. शल्यज्ञ एवं डॉ सलिल कुमार पाठक प.चि.स. शल्यज्ञ होंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड सीधी के दल में डॉ वीरेन्द्र विक्रम सिंह ख.प.चि. अधिकारी,आर.के. बड़कड़े स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी एवं

गुलाब सिंह स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी, रामपुर नैकिन के दल में डॉ ब्रज कुमार कुर्मी खं.प. चि. अधिकारी, नीरज प्रसाद द्विवेदी स.प. चि. क्षेत्र अधिकारी एवं एल.पी. माझी स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी, सिहावल के दल में डॉ शिफाली गुप्ता खं.प.चि. अधिकारी, विशाल माझी स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी एवं उमेश सिंह टेकाम स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी, मझौली के दल में डॉ ए.पी. नामदेव प.चि.स. शल्यज्ञ, आर.डी. मार्कों स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी एवं राज किशोर कोल स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी तथा कुसमी के दल में डॉ प्रशांत सिंह खं.प.चि. अधिकारी, धर्मराज सिंह स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी एवं कुमलेल सिंह स.प.चि क्षेत्र अधिकारी होंगे।

सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया है कि जिले के अंतर्गत समस्त विकासखण्ड में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। गठित समिति निर्धारित अवधि में योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

अरूणोदय बाल गृह में हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

सीधी। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे द्वारा गुरुवार दिनांक 03.04.2025 को अरूणोदय बाल गृह जिला सीधी का निरीक्षण किया गया। साथ ही विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुश्री यादव ने नालसा द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी के साथ बाल अधिकारों पर केन्द्रित योजनाओं की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त श्री शिवहरे ने बच्चों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में विस्तार से समझाया।

जिले के संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा की गयी ई-कार्यप्रणाली की शुरुआत

सीधी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुक्रम में सीधी जिले के 27 संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा गुरुवार दिनांक 03 अप्रैल 2025 को एक साथ बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में महिलाओं द्वारा सेचुरेशन, सीआईएफ रोटेशन, डिमाण्ड कलेक्शन वॉलेंस, नमो ड्रोन दीदी, पीएमएफएमई योजना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने, वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों को स्व सहायता समूह से जोड़ने, आपदा प्रबंधन योजना, व्हीपीआरपी, संभावित लखपति दीदी के अतिरिक्त ‘पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नरवाई प्रबंधन, जेण्डर, खाद्य पोषण स्वच्छता आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं समीक्षा की गयी।

विश्व हिन्दू परिषद महाकौशल प्रांत ने सौंपा ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा



खलिफ में की गई टिप्पणी को शेयर किया ये वो अपने फेसबुक से डाला है उन सभी की जाँच पड़ताल करके उन सभी के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भविष्य में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित पुजारी लाल मिश्र विभाग मंत्री, शैलेन्द्र सिंह विभाग संयोजक, राजकुमार पांडेय जिला कोषाध्यक्ष, अभिषेक सिंह जिला संयोजक, विनायक गुप्ता जिला सह सत्संग प्रमुख, राजेन्द्र सोनी नगर अध्यक्ष, माखन मिश्रा जिला बालोपासना प्रमुख, रोपन जयसवाल, उक्त जानकारी प्रचार प्रसार प्रमुख धीरेश मिश्रा ने दी।

रोजगार सहायक जोबा की सविदा सेवा समाप्त

सीधी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर अवनीश कुमार मिश्रा ग्राम रोजगार सहायक जोबा जनपद पंचायत मझौली द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति धीर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने/ सविदा शर्तों के विपरीत होने एवं आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद म.प्र. भोपाल के द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 105/उ.स.मनरेगा/जीआरएस/202 3 भोपाल दिनांक 05.10.2023 की कण्टिका 1.5 के प्रावधान अनुसार अवनीश कुमार मिश्रा ग्राम रोजगार सहायक जोबा जनपद पंचायत मझौली की सविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जलदूत के पंजीयन का दिया गया प्रशिक्षण

सीधी। जल गंगा संवर्धन अभियान में गति लाने एवं समाज की भागीदारी से कार्य को गति प्रदान करने की दृष्टि से गुरुवार दिनांक 03 अप्रैल 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला

पंचायत सीधी अंशुमन राज के द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के मैदानी अमला सेक्टर स्तर तक के व्यक्तियों के साथ संवाद कर अभियान को सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही जलदूत के रूप में पंजीयन करवाने हेतु भारत पोर्टल पर यूथ एवं वॉलंटियर के पंजीयन हेतु शैलेशा पाण्डेय परिवोजना अधिकारी मनरेगा के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक/ 06 / खनिज / 2025

सीधी, दिनांक 02/04/2025

// प्रथम सूचना //

“ म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18(1-क) ”

यह सूचित किया जाता है कि, मे0 ब्रह्मदेव मिनिरत्न, निवासी कोतरकला, पोस्ट ऑफिस के पास सीधी, तहसील-गोपवनास, द्वारा उखनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन 20.02.2025 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 08.04.2025 से 07.05.2025 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उखनिपट्टा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://ekhanijmp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	ख.क्र.	रकबा	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम	रिमाक
सीधी	गोपद वनास	अमहवा	131/1,133/2, 139/2/1,140/1,142/1, 143/1,144/2, 131/2, 133/2, 139/2/2, 142/2, 142/2, 143/2, 144/1	04.980 हे0	निजी	पत्थर (क्रशर उद्योग हेतु)	—

- उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमन्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जायेगा।
- यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनोंक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमन्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जायेगा।
- यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त भी निर्धारित समयवधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
- निर्धारित समयवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी

(खनिज शाखा)

जिला सीधी (म.प्र.)

जी-11082/25



संपादकीय

भ्रष्टाचार रोकने के लिए संसदीय समिति ने सुझाए अहम सुझाव

नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की सिफारिशें लंबे समय से की जाती रही हैं। मगर इस दिशा में किसी भी सरकार ने गंभीरता से पहल नहीं की। यह परिपाटी-सी बन गई है कि जब भी सरकार बदलती और कोई दूसरा दल सत्ता की कमान संभालता है, तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के साथ ही अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर पदस्थ करता और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाए रखने का प्रयास करता है।अब संसद की एक स्थायी समिति ने कहा है कि अधिकारियों को लंबे अरसे तक एक ही जगह पदस्थ किए रखने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित चालू वर्ष की अनुदान मांगों पर अपनी रपट पेश करते हुए कहा कि अधिकारियों की बारी-बारी से स्थानांतरण की प्रचलित नीति लागू की जानी चाहिए।संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि कुछ अधिकारी आठ-नौ वर्षों से एक ही मंत्रालय में जमे हुए हैं। कुछ अधिकारियों ने अपनी तैनाती में कुछ इस तरह चतुराई दिखाई है कि उनका पूरा कार्यकाल एक ही मंत्रालय में बीता है। करीब पंद्रह वर्ष पूर्व जब अधिकारियों की थोड़े-थोड़े समय पर तबादलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंगुलियां उठनी शुरू हुई थीं, तब प्रशासनिक आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी भी अधिकारी का तबादला तीन वर्ष से कम समय में न किया जाए, ताकि वे एक स्थान पर रह कर कुछ बेहतर काम कर सकें।मगर अब इसके उलट प्रवृत्ति विकसित हुई देखी जा रही है, तो यह भी चिंता का विषय है। निस्संदेह कुछ अधिकारी ईमानदारी और संजीदगी से काम करते हैं और उनका एक जगह लंबे समय तक बने रहना लाभदायक साबित होता है। मगर संसदीय समिति की इस बात को स्मिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि एक ही जगह लंबे समय तक बने रहने वाले अधिकारी अनियमितताओं में लिप्त हो जाते हैं। अगर बारी-बारी से अधिकारियों के तबादले की नीति रही है, तो उसका पालन करने में सरकारी को ब्यां गुरेज होना चाहिए।

पड़ोसियों की तिकड़मों से सबक सीखे भारत, हिंदुत्व की पकड़े राह?

(कमलेश पांडे)

वैसे तो इतिहास ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक मौका दिया, लेकिन संतुलित राष्ट्रवाद और अटल राष्ट्रीयता की कसौटी पर ये लोग खरे नहीं उतरे। यह कड़वा सच है कि इनके तमाम किंतु-परंतु से स्थितियां और अधिक उलझती गईं।

विभिन्न सुलगते हुए प्रादेशिक-राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और मानवीय विषयों पर भारतीय राजनेताओं, नौकरशाहों, न्यायविदों, संपादकों, समाजसेवियों और अपने-अपने पेशे में दक्ष लोगों के जो नीतिगत अंतर्विरोध हैं, वह राष्ट्रहित में तो कर्तई नहीं है। वहीं कुछ लोगों का स्पष्ट मानना है कि इन अंतर्विरोधों का असली स्रोत हमारे संविधान में अंतर्निहित है, जो 'विदेशी फूट डालो, राज करो' की नीतियों का 'देशी स्वरूप' मात्र है।

अजीब विडंबना है कि समकालीन माहौल में चिन्हित संवैधानिक नुटियों को बदलने के लिए जिस राजनीतिक कद के व्यक्ति को आगे आना चाहिए, वह अभी तक अगें नहीं आ पाया है। वैसे तो इतिहास ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक मौका दिया, लेकिन संतुलित राष्ट्रवाद और अटल राष्ट्रीयता को कसौटी पर ये लोग खरे नहीं उतरे। यह कड़वा सच है कि इनके तमाम किंतु-परंतु से स्थितियां और अधिक उलझती गईं। इससे हमारे पड़ोसी देशों का दुस्साहस बढ़ता गया और आज का भारत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चीन-अमेरिका-रूस जैसे विदेशी ताकतों पर निर्भर है।

वहीं, इनकी स्वार्थपरक बदनीयती से भारत और भारतीयता दोनों वैश्विक चक्रव्यूह में उलझ चुकी है और इस्लामिक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसीती जा रही है। लिहाजा, भारत के पास अब तीन ही विकल्प बचे हैं- पहला, वह विभिन्न चुनौतियों के वक खरी उतरी रूसी मित्रता को और मजबूत बनाए। दूसरा, चीनी चालबाजियों के खिलाफ स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाए। और तीसरा, इस्लाम विरोधी अमेरिकी गठबंधन में यदि शामिल होना है तो रूस-चीन से बेपरवाह होकर सिर्फ अमेरिका से मजबूत रिस्ते बनाए और विभाजित भारत में हिंदुत्व की भावना को मजबूत बनाए।

वहीं, यदि कोई धर्मानरपेक्षता की बात करे तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की बात उठाए, फिर धर्मानरपेक्षता अपनाए। क्योंकि इससे चीनी दाल पाकिस्तान-बांग्लादेश में नहीं गल पाएगी। ऐसा इसलिए कि अंतर्विरोधों से भरा हुआ व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र-देर-सबेर नष्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि कतिपय अंतर्विरोधों से भरा हुआ गुलाम भारत और उसके बाद अस्तित्व में आया

अजीब विडंबना है कि समकालीन माहौल में चिन्हित संवैधानिक नुटियों को बदलने के लिए जिस राजनीतिक कद के व्यक्ति को आगे आना चाहिए, वह अभी तक अगें नहीं आ पाया है। वैसे तो इतिहास ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक मौका दिया, लेकिन संतुलित राष्ट्रवाद और अटल राष्ट्रीयता की कसौटी पर ये लोग खरे नहीं उतरे। यह कड़वा सच है कि इनके तमाम किंतु-परंतु से स्थितियां और अधिक उलझती गईं। इससे हमारे पड़ोसी देशों का दुस्साहस बढ़ता गया और आज का भारत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चीन-अमेरिका-रूस जैसे विदेशी ताकतों पर निर्भर है।



आजाद भारत भी अपने अमृतकाल यानी न्यू इंडिया के जमाने में 2047 के बाद भी उन्हीं स्थितियों-परिस्थितियों से गुजरे, जो इसकी 800 सालों की गुलामी और मर्मांतक राष्ट्र-विभाजन की मौलिक वजह समझी गई हैं।

इसलिए मौलिक व ऐतिहासिक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब राजनेता-नौकरशाह-न्यायविद, सैन्य हुकमरान और अपने-अपने पेशे के दक्ष लोग जाति-धर्म मुक्त होकर एक सशक्त और उदार भारत की नींव रखना चाहेंगे, जहां हिन्दू हितों से कोई समझौता नहीं हो। जैसे कि पाकिस्तान व बंगलादेश में मुस्लिम हितों से कोई समझौता नहीं किया जाता है। गुजरते दशकों में या आजकल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और मीडिया में चीन-बांग्लादेश-पाकिस्तान की जारी तिकड़मों से भारत को सबक लेना चाहिए और नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान आदि की भी नकेल कसते हुए भारत के समग्र हित को साधने की स्पष्ट रणनीति तैयार करनी चाहिए। यह सबकुछ तभी सम्भव होगा जब हमारी सरकार हिंदुत्व की मजबूत राह पकड़ेगी और चीनी शह पर खलता प्रदर्शित कर रहे पड़ोसियों को जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएगी। इसके लिए साम, दान, दंड, भेद की नीतियों की जरूरत भी पड़े तो उसे अपनाने में हमारी सरकार को नहीं हिचकना चाहिए।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि विविधता

हमारी खूबसूरती है, लेकिन यही बात धर्मानरपेक्षता पर तब लागू होगी जब पाकिस्तान-बांग्लादेश का विलय भारत में हो जाए। जबतक जर्मनी और इटली की तरह इंडिया का भी एकीकरण नहीं हो जाता, तब तक हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है और समकालीन चीनी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तिकड़मों का जवाब भी हिंदूवादी रणनीति के जरिए ही दिया जा सकता है। इस बात में किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेद में स्पष्ट कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति। यानी जिसके मन में संशय हो, उसका विनाश निश्चित है। इस नजरिए से केंद्रीय और विभिन्न राज्यों की सत्ता में मजबूत हुई भाजपा और उसकी मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विभिन्न मौकों पर अड़िग हिंदुत्व को लेकर जो संशय दिखाए जा रहे हैं, उससे भविष्य में 'कांग्रेस' मजबूत होगी और भाजपा की दुर्गीत कांग्रेस से ज्यादा हो सकती है। क्योंकि भारतीय मतदाता बहुत ही मंजे हुए निर्णय लेते हैं।

आखिर 'पारसी वधू' पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वाली गलतियां भी 'वैश्य बहदुर' मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुहराएंगे तो फिर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रह जाएगा? शायद अंतर है भी नहीं, क्योंकि सत्ता में आते ही सुविधाभोगी नौकरशाही और उद्योगपतियों का 'गिरोह' कतिपय अंतरराष्ट्रीय संधियों/मजबूरियों जनित लाभ-हानि का वास्ता देकर राजनीतिक हृदय

चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों की बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सफलता मिल रही है।

आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सकें। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देश में खेती किसानों का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके।

विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है। औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है।

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एंव छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है।

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की है और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा।

भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और



इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के सफलता मिली है।

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल

संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में सीमांत एंव छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्थिती को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के

आज का राशिफल



मेष

आज दिन अच्छा है और आपको जीवनसाथी का साथ मिलेगा। राशि स्वामी मंगल ग्रह सौम्य ग्रहों के साथ है। आपको हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। शाम के समय आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, लेकिन संतान की तरफ से निराशाजनक खबर मिल सकती है। रात का समय प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी में बीतेगा।



मिथुन

आज सावधान रहने की जरूरत है। आपको कोई कीमती वस्तु के खोने या चोरी होने का डर है। आपको बिना विश्वास के कोई काम न करने की सलाह है। शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से मन खुश होगा और आपका कोई व।



सिंह

आज लाभ होगा और आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने से ख़ास लाभ होगा। आपको वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी और आपके लिए शिक्षा और प्रतियोगिता में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है और आंखों में द्रिक्क हो सकती है।



वृष

आज दिन संतोष और शांति का है और राजनीति के क्षेत्र में आपके सभी प्रयास सफल होंगे। नए समझौते आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे और आपको ऑफिस के कार्य में लाभ के साथ ही संतोष भी हासिल होगा। रात में कुछ अग्रिय लोगों में मिलने से परेशानी हो सकती है, सावधान रहें।



कर्क

आज दिन उत्तम है और आपको उत्तम संपत्ति की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और राज्य में मान-सम्मान बढ़ेगा। आपकी संतान से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है और आपके धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यात्रा करना सुखद और लाभदायक रहेगा।



कन्या

आज दिन बहुत अच्छा है और आपको व्यापार में आपके सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। दोपहर के बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है। रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी।



तुला

आज दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपके घर में सुखद वातावरण रहेगा। कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। आपको पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा। आपके विरोधी परास्त होंगे। आपके लिए यात्रा करने के योग हैं और आपके सम्मान में वृद्धि के योग हैं।



धनु

आज दिन अच्छा है। विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे। आपको शासन और सत्ता पक्ष से निकटता का लाभ मिलेगा और आपको ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। विरोधी भी आपको प्रशंसा करेंगे। आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आपको धन सम्मान में वृद्धि होगी।



कुंभ

आज धन लाभ होगा। आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। कोई बुरी खबर सुनकर आपको अचानक राय पर जाना पड़ सकता है। आपके लिए धन सम्मान में वृद्धि होगी। सावधान रहें और झगड़े से बचें। आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी और योजनाएं सफल होंगी। आपको मित्रों का साथ मिलेगा।



मीन

आज धन लाभ होगा। आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। कोई बुरी खबर सुनकर आपको अचानक राय पर जाना पड़ सकता है। आपके लिए धन सम्मान में वृद्धि होगी। सावधान रहें और झगड़े से बचें। आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी और योजनाएं सफल होंगी। आपको मित्रों का साथ मिलेगा।



वृश्चिक

आज लाभ का दिन है। आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी और रुकी योजनाएं पूर्ण होंगी। आपको डॉक्टर के पास कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बीमारी की हालत में भी आपको ज्यादा चलन-फिरन पड़ सकता है। आपको काफी दौड़भाग करनी पड़ सकती है। धन सम्मान के मामले में लाभ होगा।



मकर

आज धन सम्मान में लाभ होगा। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अपने कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। शाम के समय किसी झगड़े में न पड़ें। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और सफलता के योग हैं। प्रिय अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिलेगा।



आज दिन मिला-जुला रहेगा। आपको अपने बच्चों की चिंता रहेगी और आपको अपने घर में या फिर रिश्तेदारों में बहनों और साले से लेन-देन का सकेत भी सलाह है। आप धार्मिक यात्रा पर जा करने हैं और पुण्य कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। यात्रा में सावधान रहें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है।

तर्ग पहली 5690

1	2	3	4	5	6
7		8	9		
10		11	12		
	13	14		15	
16		17	18		
19	20		21		
22		23		24	
25				26	

संकेत: बाएं से दाएं

- पुन्य विभूषण से सम्मानित थे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने इंग्लिश सैनिकों के लिए पार किया (5)
- थोड़ा, अल्प, न्यून (2)
- मंगल ग्रह इस राशि का बलाघा गया है, इंद्रधनुष के रंगों में से एक (2)
- बालचीत करने का गुण या हुनर (5)
- हाथी को यह भी कहते हैं, पर्वत से उत्पन्न (3)
- लिकन, सिकुड़न, मरोड़ (2)
- वाक्प्रचार, वाक्पथ (4)
- नगड्डा, छद्मता (2)
- अपराध करना, पीटना (3)
- उपहार-पुष्पहार, यह अधिभोगी जीनात अमन की पहली किरण थी (1970) (4)
- सल्ल, भला, सज्जन (2)
- आकल, विपत्ति, भूत-प्रेत की बाधा (2)
- उचित, मुनासिब (3)
- सौर, किनारा (2)
- किरात के समय घर को पहचाने जाने वाला मुकुट, शिरोभूषण (2)
- ऊपर से नीचे
- शरान्तस्य सन्धान, तुलनात्मकरूप से

देखा जाना (3)

- परिचय, सर्विद, धिक्कृत (2)
- देखने में सैध लगाकर चोरी करने वाला (5)
- कडुआ, अश्विज (2)
- चोट देने की पाशता (5)
- समय का सबसे छोटा भाग, धन (2)
- पांचवा लोक जहां से मृत्यु उत्पन्न होते है (2)
- कुलीबन्धन, बेंड्या, यह जो कुली लड़ता हो (5)
- संसील, साथ, संत (4)
- तकदीर, भाग्य, प्रारम्भ (3)
- माग, मस्तक (3)
- राज भोज की नगरी (2)

तर्ग पहली 5689 का हल

श	र	ख	ड	स	म	ता
वा	म	का	म	च	सा	ऊ
	द	र	मु			
म	घ	ना	व	ज		
ई	ख	न	न	घा	न	
आ	क्षि	र	क	प	ट	ता
ज	ना	व	वी	छा		

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली सरकार का फैसला, सभी सरकारी इमारतों का होगा फायर ऑडिट नईदिल्ली, एजेंसी। गमीं के मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत राष्ट्रीय राजधानी स्थित सभी सरकारी इमारतों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का फायर ऑडिट 15 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब दिल्ली की सरकारी इमारतों में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। दरअसल दिल्ली में गमीं के मौसम में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसका उद्देश्य आग लगने की घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फायर ऑडिट के तहत, प्रत्येक सरकारी इमारत में आग से बचाव के उपायों की समीक्षा की जाएगी। इसमें इमारतों में मौजूद अग्निशामक उपकरणों की जांच, एग्जिट रूट्स का सत्यापन और आग से संबंधित अन्य सुरक्षा मानकों की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये स्थान अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं और आग लगने के मामले में खतरा अधिक होता है। दिल्ली सरकार इस फायर ऑडिट प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए हरसंभव कोशिश करेगी, ताकि गमीं के मौसम में किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

भारतीय रेलवे ने लगाए 2,249 सोलर पावर प्लांट, हरित ऊर्जा की ओर बढ़ा कदम

नईदिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण और रिन्युएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में 2,249 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार को लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पिछले पांच वर्षों में रेलवे ने 1,489 सोलर यूनिट स्थापित किए, जो उससे पहले के पांच वर्षों में लगे 628 यूनिट्स की तुलना में 2.3 गुना अधिक है। इस पहल में राजस्थान सबसे आगे है, जहां अब तक 275 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हैं। भारतीय रेलवे रिन्युएबल एनर्जी को अपनाने के लिए विभिन्न ऊर्जा खरीद मॉडलों का उपयोग कर रहा है। इनमें राउड द वर्ल्ड का उपयोग कर रहा है। इनमें राउड द वर्ल्ड का उपयोग कर रहा है, जो सौर और पवन ऊर्जा को शामिल करता है। अधिकतर सोलर प्लांट डेवलपर मोड में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना के सामने कई चुनौतियां आईं, जैसे नियामक बाधाएं, बिजली निकासी और कनेक्टिविटी की समस्याएं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने राज्य सरकारों और ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। अब तक रेलवे ने 209 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित कर ली है और इसे लगातार बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे का यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का बनेगा रोड नेटवर्क, आसपास के गांवों से जुड़ेगी कॉलोनी

मेरठ, एजेंसी। मेरठ में दिल्ली रोड पर बनने जा रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए बहुत जल्द रोड नेटवर्क बनने जा रहा है। राइट्स ने इसके लिए रोड का जोनल प्लान तैयार कर लिया है। कॉलोनी को आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए फीडर रोड तैयार करना है। इसके साथ ही कॉलोनी में गुप्त हाउसिंग और फ्लैट्स फेक्टरी के प्लॉटों के साथ ही 10 फीसदी प्लॉट इंडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए भी आरक्षित किए जाने हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण नेले-आउट पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरठ समेत एनसीआर के लोगों के घरों का सपना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की नीय में मेडा दिल्ली रोड पर 300 हेक्टेयर जमीन पर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने जा रहा है। इस टाउनशिप में आवासीय यूनिट के अलावा पलैटेंट फेक्टरी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, कॉरपोरेट जॉब्स आदि के लिए भूखंड काटे जाएंगे। टाउनशिप के लिए चार गांवों की जमीन खरीदी जा रही है। अभी तक करीब 98 हेक्टेयर जमीन का खरीद हो चुकी है, जिस पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मेडा अब इस टाउनशिप के लिए रोड नेटवर्क तैयार करने जा रहा है। मेडा की कंसलटंसी एजेंसी राइट्स ने सड़कों का जो जोनल प्लान तैयार किया है उसी प्लान से टाउनशिप का रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। टाउनशिप की उपयोगिता का लाभ शत प्रतिशत लेने के लिए आसपास फीडर रोड निर्माण बहुत जरूरी है। मेडा वीसी अभिषेक पांडेय ने बताया कि टाउनशिप पर जल्द विकास कार्य शुरू होना है। सबसे पहले रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके बाद सीवर लाइन और पार्क आदि तैयार किए जाएंगे।

नेहरू-एडविना की चिट्ठियां वापस दे दीजिए, पीएम म्यूजियम ने सोनिया गांधी से मांगे कई निजी दस्तावेज

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने की मांग की है। इनमें नेहरू-एडविना की चिट्ठियां भी शामिल हैं। ये दस्तावेज मई 2008 में सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एनएमएमएल) से वापस लिए गए थे। पीएमएमएल ने अपने पत्र में कहा है कि इन दस्तावेजों को शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाए ताकि आधुनिक भारतीय इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएमएमएल ने सोनिया गांधी से नेहरू से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण पत्राचार दान करने का भी अनुरोध किया है, जिससे आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिल सके। सोनिया गांधी के कार्यालय ने इस पत्र पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पीएम म्यूजियम ने गांधी परिवार से भारत के पहले पीएम से जुड़े निजी दस्तावेजों की मांग की है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री संग्रहालय ने गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू द्वारा एडविना माउंटबेटन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र वापस करने का



अनुरोध किया था। अनुरोध में उनसे इन दस्तावेजों को वापस करने या कम से कम उनकी डिजिटल या फोटोग्राफिक प्रतियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। नेहरू के दस्तावेजों पर चर्चा : फरवरी 2024 में हुए पिछले वार्षिक आम बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन यह पहली बार है जब पीएमएमएल ने इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से सोनिया गांधी के सामने रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक में, पीएमएमएल के संग्रह में मौजूद नेहरू के निजी दस्तावेजों पर चर्चा हुई थी। इनमें से 51 बॉक्स मई 2008 में सोनिया गांधी ने वापस ले लिए थे। बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इन दस्तावेजों को फिर से वापस लिया जाना चाहिए और उनके स्वामित्व,

संरक्षण, कॉपीराइट और उपयोग को लेकर कानूनी राय ली जानी चाहिए। महत्वपूर्ण पत्राचार शामिल : पीएमएमएल के रिकॉर्ड के अनुसार, सोनिया गांधी द्वारा वापस लिए गए दस्तावेजों में नेहरू और जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित और जगजीवन राम के बीच हुए पत्राचार शामिल हैं। इस वर्ष 15 जनवरी को पीएमएमएल सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फिल्म निर्माता शेखर कपूर और

संस्कार भारती के वासुदेव कामथ को भी समिति में शामिल किया गया है। नई पीएमएमएल सोसाइटी की पहली वार्षिक आम बैठक कुछ हफ्तों में होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र के बाद भविष्य में इस मामले में कोई ठोस कदम उठया जा सकता है। अन्य प्रधानमंत्रियों के दस्तावेजों पर भी ध्यान : इस बीच, पीएमएमएल ने भारत के सभी पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्रियों के परिवारों और कार्यालयों को पत्र लिखकर उनसे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अब तक, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पोते ने इस पत्र का जवाब दिया है और उनके जीवन से जुड़े कुछ दस्तावेज और कलाकृतियों को दान करने की सहमति जताई है। 2008 में दस्तावेजों को वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि मार्च 2008 में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एम वी राजन ने पीएमएमएल का दौरा किया था। उन्होंने नेहरू संग्रह से निजी और सरकारी कागजातों को अलग किया, और सभी निजी दस्तावेजों को 51 बक्सों में पैक कर 5 मई 2008 को सोनिया गांधी को भेज दिया गया। यह प्रक्रिया तत्कालीन निदेशक की मंजूरी से हुई थी।

एकनाथ शिंदे के पास जाएगी हर फाइल, अजित पवार से ज्यादा हुई पावर, सारी शिकायतें दूर



मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार में बीते कई महीनों से चली आ रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो वह होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन वह भी नहीं मिला तो कुछ मंत्रालय लेकर डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद ही उनकी नाराजगी बनी ही रही। कभी प्रभारी मंत्रियों को लेकर तो कभी मंत्रालयों के फैसलों को लेकर वह खफा दिखते थे। एक मलाल यह भी रहा कि अजित पवार को उनसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की कोई भी फाइल उनसे होकर ही सीएम देवेंद्र फडणवीस तक जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद से अजित पवार के पास फाइल जाती थी क्योंकि वह वित्त मंत्री थे और फिर सीएम फडणवीस उसे देखते थे। अब नई व्यवस्था आ गई है, जिसके तहत पहले फाइल अजित पवार पर ही जाएगी। फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास फाइलें आएंगी और उनके पास करने के बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचेंगी। इससे पहले जब एकनाथ शिंदे ही सीएम थे तो यह व्यवस्था थी कि पहले अजित पवार के पास फाइल पहुंचती थी और फिर देवेंद्र फडणवीस के पास से होते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचती थी। अब एक बार फिर से वैसी ही व्यवस्था है, बस क्रम बदल गया। अब फडणवीस सीएम हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अजित पवार से शिवसेना लीडर का कद बढ़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक की ओर से आदेश जारी किया गया है।

भारत ने चिली को वेक्स 2025 के लिए निमंत्रण दिया, मुंबई में 1 से 4 मई को पहला वेक्स समिट

नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बुधवार को नई दिल्ली में चिली की संस्कृति, कला और विरासत मंत्री कैरोलिना ओरेंदो से मुलाकात की। चिली की संस्कृति मंत्री राष्ट्रपति ग्रेन्नियल बोरिक फॉन्ट की 5 दिन की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में हैं। एल मुरुगन ने इस दौरान उन्हें आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। साथ ही उन्हें भारतीय पेंटिंग भेंट की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में चिली के प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया, जिनमें चिली के दूतावास में तृतीय सचिव मार्टिन मारमेज, विदेश मंत्रालय में अवर सचिव लक्ष्मी चंद्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर अजय नागभूषण एम एन शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान व्यापक चर्चा की। भारत मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहाँ देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली प्रतिभाएँ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से आकर्षक विषय-वस्तु का निर्माण करती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रथम वेक्स समिट 1 से 4 मई, 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित करने जा रहा है।

शिमला में पानी महंगा, जल निगम ने बढ़ाया टैरिफ, अब कितना चुकाना होगा बिल?

शिमला, एजेंसी। हिमाचल की राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में उपभोक्ताओं को पानी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) ने पानी पर लगने वाले टैरिफ में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई दरें घरेलू, वाणिज्यिक और धार्मिक संस्थानों सहित सभी उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। शिमला नगर निगम (एसएमसी) क्षेत्र के भीतर और एसएमसी क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अलग-अलग होंगे। पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, 0-20 केएल स्लैब पर संशोधित शुल्क 21.23 रुपये प्रति किलो लीटर, 20-30 स्लैब पर 36.61 रुपये प्रति किलोलीटर और नगर निगम

सीमा के भीतर उपभोक्ताओं के लिए 30 किलोलीटर से अधिक खपत के लिए 69.89 रुपये होगा। यही नहीं न्यूनतम मेट्रिक्स चार्ज बढ़ाकर 121 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोषपूर्ण मीटर के लिए चार्ज 488.48 रुपये प्रति माह होगा। शिमला नगर निगम क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 48.31 रुपये होगा। इसके बाद 20-30 किलोलीटर स्लैब के लिए 73.21 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक के लिए 102.49 रुपये होगा जबकि शिमला एमसी की सीमा के बाहर घरेलू जल कनेक्शन के लिए न्यूनतम मेट्रिक्स चार्ज 242 रुपये प्रति माह होगा। दोषपूर्ण मीटर के लिए रेट 1,948.58 रुपये प्रति माह होगा। शिमला नगर निगम सीमा के



भीतर और बाहर होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए प्रति किलोलीटर चार्ज 20 और बाहर वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए चार्ज 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 116.93 रुपये, 30-75 किलोलीटर के लिए 155.88 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक की खपत के लिए 214.34 रुपये होगा। प्लग किए गए कनेक्शन के मामले में 242 रुपये प्रति माह जबकि दोषपूर्ण

मीटर के लिए 8,557.67 रुपये प्रति माह का चार्ज लिया जाएगा। एसएमसी सीमा के भीतर और बाहर वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए चार्ज 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 58.56 रुपये, 30 किलोलीटर के लिए 92.09 रुपये, 75 किलोलीटर के लिए 122.40 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक के लिए 168.38 रुपये होगा। एसएमसी सीमा के भीतर और

बाहर सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और धार्मिक स्थलों के लिए संशोधित चार्ज 92.25 रुपये प्रति किलोलीटर होगा और सभी श्रेणियों के लिए पानी के बिल का 30 फीसदी सीवरेंज चार्ज के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा, 2,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैंकर चार्ज 1,797 रुपये और 1,331 रुपये कर दिया गया है और 4,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए 3,593 रुपये और 2,662 रुपये वसूल जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि 6,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए संशोधित चार्ज घरेलू उपयोग के लिए 3,993 रुपये और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 5,390.55 रुपये होगा।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, विफल रही वार्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने के बाद भाजपा नीत केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह दोनों सरकारों के बीच चल रही वार्ता की पूर्ण विफलता को दर्शाता है। अपने हमलों को तेज करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस सरकार को अपनी रीढ़ विकसित करने और अमेरिका के सामने खड़ा होने की जरूरत है।



तिवारी ने एएनआई से कहा, यह अमेरिका और भारत सरकार के बीच चल रही वार्ता की पूर्ण विफलता को दर्शाता है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारे छात्रों को निष्कासित किया है और बिना किसी उकसावे के वीजा रद्द कर दिया है, और सरकार पूरी तरह चुप है... सरकार को हिम्मत दिखाने और अमेरिका के सामने खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र की आलोचना की और मोदी सरकार को कहीं है? वित्त और वाणिज्य मंत्री कहीं हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वे फिर से कार्रवाई में गायब क्यों हैं? अमेरिकी चुप्पी और निष्क्रियता पर सवाल उठाया।

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुरजेवाला ने कहा, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया +27% शुल्क बुधवार, 3 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है! इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और कंप्यूटर, रसायन, परिधान, यार्न और कालीन, मछली, मांस और प्रसंस्कृत समुद्री भोजन, भगवान और आभूषण और कई अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। मोदी सरकार कहीं है? वित्त और वाणिज्य मंत्री कहीं हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वे फिर से कार्रवाई में गायब क्यों हैं? अमेरिकी चुप्पी और निष्क्रियता पर सवाल उठाया।

(स्थानीय समय) को नए आयात शुल्क की घोषणा की, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले दरों की रूपरेखा बताई गई, जिसमें भारत पर 26 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना महान मित्र बताते हुए ट्रम्प ने कहा कि भारत अमेरिका से 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, जबकि हम उनसे लगभग कुछ भी शुल्क नहीं लेते हैं। ट्रम्प ने यह घोषणा मेक अमेरिका वेल्थी ओगेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, भारत बहुत-बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी-अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।

सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग, राज्यसभा में गूंजा मुद्दा; 2008 में मिला था पद्मभूषण

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा में बुधवार को तुणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। हालांकि तुणमूल सदस्य ने दावा किया कि गुजरात के एक राजनीतिज्ञ सुनीता के करीबी रिश्तेदार थे। इस पर विरोध जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तुणमूल सदस्य के कथन के इस हिस्से को कार्यवाही से हटाने की मांग की। सुनीता की उपलब्धियों की सराहना करते हुए तुणमूल सदस्य

मोहम्मद नदीमुल हक ने शून्यकाल के दौरान कहा कि 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता 18 मार्च को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आईं। उन्होंने कहा कि सुनीता की यह उपलब्धि सहाहनीय है और पूरा भारत इस पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि उनकी यह उपलब्धि 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भी गौरवान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय मूल की सुनीता की वापसी पर कहा था कि भारत की बेटी वापस लौट आई हैं। हक ने कहा कि सुनीता 2007 में भारत आई थीं और तब



उन्हें कई सम्मान दिए गए थे। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि सुनीता ने कुछ समय पहले भारत आने की इच्छा जताई थी।

तुणमूल सदस्य ने कहा कि तब सुनीता ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा था कि वह उनका सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता कुछ राज्यों में गई थीं लेकिन उन राज्यों की सरकारों ने उन्हें सम्मानित नहीं किया था। हक ने कहा कि गुजरात के एक राजनीतिज्ञ सुनीता के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने दिवंगत राजनीतिज्ञ का नाम भी लिया जो गुजरात में मंत्री थे और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी के लिए भारत रत्न की मांग करना एक अलग बात है किंतु इसमें किसी दिवंगत नेता

का संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा "उस व्यक्ति का संदर्भ देना सही नहीं है जो अब हमारे साथ नहीं है।" उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि तुणमूल सदस्य के कथन का वह हिस्सा सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि जो भी हिस्सा अप्रासंगिक होगा, उसे मुंडारी सहित कुछ भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में पेशन भोगियों को पेशन मिलने में खले जाने की मांग की। इसी पार्टी की सुलता देव ने पशुओं के साथ क्रूरता का मुद्दा उच्च सदन में उठाया और सरकार से इस संबंध में कड़े कानून बनाए जाने की मांग की।

मिलने में विलंब से पेशन भोगियों को खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने नदियों में प्रदूषण किया का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे आम लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। शून्यकाल में ही बीजद के सस्मित पात्रा ने कुछ जर्जनिजियों द्वारा बोली जाने वाली हो और मुंडारी सहित कुछ भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में खले जाने की मांग की। इसी पार्टी की सुलता देव ने पशुओं के साथ क्रूरता का मुद्दा उच्च सदन में उठाया और सरकार से इस संबंध में कड़े कानून बनाए जाने की मांग की।

कलेक्टर ने अजयगढ़ में ली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने बुधवार को आकांक्षी विकासखण्ड अजयगढ़ के जनपद पंचायत सभाकक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं विभागवार निर्धारित संकेतकों के आधार पर अद्यतन प्रगति की विभागवार समीक्षा की और लक्ष्य अनुरूप समय-सीमा में योजनाओं के शत प्रतिशत सेचुरेशन सहित पात्र हितग्राहियों को अन्य योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा कर विभिन्न सभागी विभागों के समन्वय से जल स्रोतों के पुनरूद्धार के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर श्री कुमार ने समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को समस्त हितग्राहीमूलक कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि आवास प्लस योजना में 30 अप्रैल



तक बढ़ाई गई समयावधि में अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत जनजातीय परिवारों के नाम भी जोड़े जाएं। कोई भी पात्र व्यक्ति के आवास योजना से वंचित होने पर संबंधित के विरुद्ध जवाबदेही तय कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अजयगढ़ विकासखण्ड में 250 से अधिक आबादी के समस्त बसाहटों में प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत

सड़क निर्माण के संबंध में एप के जरिए आवश्यक सर्वे सहित ग्राम पंचायतों में नवीन स्वीकृत अटल सुशासन भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति तथा आंगनबाड़ी एवं सामुदायिक भवनों की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत तृतीय किस्त प्राप्त हितग्राहियों के कार्य पूर्णता व सर्वे की भी समीक्षा की।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्मकाल के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय पूर्व आवश्यक तैयारी कर ली जाए। इसके लिए मैदानी अमले को भी पाबंद करें। विभिन्न नल जल योजनाओं के संचालन एवं कर संग्रहण सहित समग्र एवं पेंशन हितग्राहियों की ई-केवायसी कार्य के प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही अजयगढ़

विकासखण्ड में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में भी बैठक के दौरान चर्चा कर निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, एसडीएम आलोक मार्को, जनपद पंचायत सीईओ सतीश नागवंशी, परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार सहित सहायक यंत्री, उपयंत्री, राजस्व निरीक्षक, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बैठक में समस्त पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित होने पर सराहना भी की और सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। इसके अलावा कम प्रगति वाले सचिव एवं रोजगार सहायक से चर्चा कर तय समय सीमा में विकास कार्यों को पूर्ण करने तथा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर द्वारा गुरुवार को शाहनगर एवं पर्वई विकासखण्ड तथा शुक्रवार को गुनौर एवं पन्ना विकासखण्ड में भी समीक्षा बैठक ली जाएगी।

कृष्णा कल्याणपुर में शराब दुकान खोले जाने को लेकर लोगों ने किया जमकर विरोध

पन्ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अनेक धार्मिक नगरों में शराब दुकान बंद कराई गई इसी कड़ी में धार्मिक स्थल पन्ना जिला मुख्यालय में भी चार शराब दुकानबंद कर दी गई तथा उन्हें नहीं खोलने का वादा किया था लेकिन ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिली भगत से के चलते जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर शराब दुकान खोल दी गई जिसका लोगों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा दहलान चौकी के नाम पर स्वीकृत दुकान जनकपुर रोड कृष्णा कल्याणपुर में शराब दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के लोगों ने जमकर विरोध किया तथा रोड पर बैठकर चक्का जाम किया एवं कहा कि यदि उक्त शराब दुकान बंद नहीं की जाती है तो हम इसका लगातार विरोध करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की समझायाइस के बाद चक्का जाम बंद कर दिया है लेकिन लोगों का कहना है कि इस स्थान पर यह शराब दुकान संचालित नहीं की जाएगी एक दिन पूर्व जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सोपा गया था जिस पर मांग रखी गई थी कि शराब दुकान संचालित ना की जाए आगे देखा है प्रशासन क्या निर्णय लेता है।

समूह जल प्रदाय योजना के निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण



पन्ना। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने बुधवार को जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वित समूह जल प्रदाय परियोजना सिंघौरा-2 के निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों का ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में अवलोकन कर शेष कार्यों को अविलंब पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिप सीईओ ने अजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम कुंवरपुर में सिंघौरा जल प्रदाय योजना के प्रगतिरत एवं संचालित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर जल शोधन

संयंत्र का अवलोकन किया। सभी अवयवों की प्रगति का जायजा लेकर योजना के प्रारूप की जानकारी प्राप्त की। महाप्रबंधक जल निगम शिवम सिन्हा द्वारा गुणवत्ता निर्धारण के लिए प्रयोगशाला में सामग्री परीक्षण और सेफ्टी पार्क के साथ जल सोधन संयंत्र के लेआउट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सीईओ ने जल सोधन संयंत्र प्रांगण में पौधरोपण भी किया। उल्लेखनीय है कि उक्त जल प्रदाय योजना के माध्यम से पन्ना एवं गुनौर विकासखण्ड के 415 गांवों में पेयजल प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर ने जांच दल का किया गठन

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं अंतर जिला व जिले में उपार्जन केन्द्रों से प्रदाय धान के सत्यापन एवं जांच कार्यवाही के लिए जांच दल गठित किया है। संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम को जांच दल के अध्यक्ष एवं जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया को संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। दल में सहायक आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तथा म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को सदस्य नियुक्त किया गया है। जांच दल को निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर सुक्ष्मता से जांच कर वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन संयुक्त हस्ताक्षर से सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

तहसील मध्यस्थता केन्द्र अजयगढ़ का निरीक्षण कर दिए निर्देश



पन्ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजकुमार गौड़ ने आज जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन बी.के. त्रिपाठी के साथ अजयगढ़ के निर्माणाधीन तहसील मध्यस्थता केन्द्र का निरीक्षण किया। तहसील विधिक सेवा समिति अजयगढ़ को भवन

हस्तांतरण के पूर्व निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सुविधाओं में मिली कमियों का जायजा लेकर कार्यपालन यंत्री को अविलंब आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सहित अन्य आवश्यक सुझाव दिए गए। निरीक्षण के बाद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं मध्यस्थता योजना सहित आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही लोक अदालत के वृहद प्रचार-प्रसार की अपील भी की गई।

अग्निकांड में नष्ट हुई गेहूं की फसल का पुलिस व राजस्व अधिकारियों ने किया निरीक्षण, आग लगाने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने का दिया आश्वासन

किसानों ने कहा समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो जलने से बच सकती थी गेहूं की फसल

जिले के देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत ग्राम मुटकला में बीती रात खेत में कटी रखी लगभग तीन एकड़ खेत की गेहूं की लगभग पर एक व्यक्ति के द्वारा द्वेष भावना के चलते आग लगा दी गई, आग लगने के बाद खेत के मालिक सुम्पेर सिंह यादव के द्वारा आरोपी को भागते हुए देखा गया, मामले की सूचना तत्काल किसान ने अपने दोनों पुत्रों अरविंद सिंह यादव और संतोष सिंह यादव को दी संतोष सिंह यादव सकरिया एयरपोर्ट में सिस्कोरिटी गार्ड की जांच करते हैं और अरविंद सिंह यादव पन्ना में रहते हैं। लगभग 10



से 15 मिनट में दोनों पहुंच गए लेकिन फायर ब्रिगेड और डायल हंड्रेड जैसे इमरजेंसी दल दो घंटे बीतने के बाद भी नहीं पहुंचे, लगभग 2 घंटे बाद देवेंद्र नगर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड

आग लगाने वाले आरोपी के प्रति लोगों में भारी आक्रोश था जागरूक नागरिकों के द्वारा पुलिस का इंतजार किया जा रहा था ताकि कोई घटना घटित ना हो सके पुलिस अधीक्षक को फोन करने के बाद देवेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगजनि के संबंध में लोगों से पूछताछ की दूसरे दिन देवेंद्र नगर नायब तहसीलदार कोमल आठिया, पटवारी देवेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक आरके प्रजापति सहित पुलिस और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया इसके अलावा पुलिस के द्वारा आग लगाने वाले आरोपी को अभिरक्षा में लेकर

पूछताछ की जा रही है। अरविंद सिंह यादव ने कहा है कि गर्मियों में आगजनी की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं, कुछ लोग द्वेष भावना से आग लगाते हैं तो कुछ घटनाएं अन्य कारणों से होती हैं, ऐसे में फायर ब्रिगेड और डायल जैसे इमरजेंसी दल अगर इस प्रकार की लापरवाही करते हैं तो घटनाओं के दौरान नुकसान को रोकना मुश्किल होता है इसलिए फायर ब्रिगेड और डायल हंड्रेड जैसे वाहनों और उनके दल को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए।

औषधि निरीक्षक के नाम पर दवा दुकानों से कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है : श्रीकांत

पन्ना। औषधि निरीक्षक के नाम पर अवैध वसूली करने को लेकर ग्रामक खबर फैलाई गई जो पूर्णता गलत है इस प्रकार की कोई अवैध वसूली किसी के द्वारा नहीं की जा रही है और ना ही दवा विक्रेताओं द्वारा कोई राशि दी गई है संगठन के द्वारा समय-समय पर संगठन का उद्देश्य एवं सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसको लेकर जिला संगठन द्वारा अपने ही सदस्यों से राशि एकत्रित करके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसी को लेकर सूची तैयार की गई थी लेकिन किसी के द्वारा संगठन को बंदनाम करने एवं

औषधि निरीक्षक पर अनैतिक दबाव बनाने को लेकर बंदनाम करने की साजिश की गई है जो गलत है जिले में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट मध्य प्रदेश फार्मसी कार्सिल एक्ट के तहत विधिवत औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं कहीं भी किसी प्रकार नियम विपरीत काम नहीं किया जाता है जिससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को राशि या चंदा देने की जरूरत पड़े अध्यक्ष श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि इस प्रकार से किसी को बंदनाम करना गलत बात है पन्ना जिले में दवा व्यवसाय एकदम साफ एवं सुरक्षित ढंग से किया जाता है।

जनकपुर में आम फल बहार की नीलामी 7 अप्रैल को

पन्ना। उद्यानिकी विभाग द्वारा सोमवार, 7 अप्रैल को जनकपुर स्थित रंसीरी में अपराह्न 3 बजे कलमी आम फल बहार की नीलामी की जाएगी। इस संबंध में इच्छुक क्रेतागण को उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेने के संबंध में सूचित किया गया है। नीलामी के पूर्व कार्यालयीन समय में आम फल बहार का अवलोकन कर सकते हैं। वांछनीय शर्त अथवा अन्य जानकारी के लिए उद्यान को विभाग के जिला कार्यालय अथवा रोपणी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

पुलिस द्वारा 09 वर्ष से फरार स्थाई वारंटी को किया गया गिरफ्तार

पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्णा एस. थोटा द्वारा स्थायी वारंटों की अधिक से अधिक तामीली हेतु पन्ना जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना चौहान व जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इसी

तारतम्य में तारतम्य में थाना अमानगंज पुलिस द्वारा पिछले 09 वर्षों से फरार आरोपी राम प्रताप विश्वकर्मा पिता मिट्ठू लाल विश्वकर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी नयापुरा द्वारी थाना अमानगंज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय पन्ना के प्रकरण क्रमांक 663/16 धारा 25 बी आम्स एक्ट मे स्थाई वारंट जारी किया गया था। दिनांक 02/04/2025 को अमानगंज पुलिस के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर उक्त वारण्टी

को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय के आदेश से जिला जेल पन्ना में दाखिल किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री प्रधान आरक्षक राजीव मिश्रा, मुकेश शर्मा, मुकेश सोनी, आरक्षक द्वारका प्रसाद, गिरधारी साहू, का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उपरोक्त पुलिस टीम के कार्य को सराहना की गई है।

जल स्रोतों में चलाया गया स्वच्छता अभियान

पन्ना। शासन के निर्देशानुसार पन्ना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल स्रोतों के जीर्णोद्धार सहित उनकी साफ सफाई का कार्य संचालित किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 30 जून तक निरंतर चलेगा। बुधवार को जन अभियान परिषद के स्वयंसेवकों द्वारा समस्त विकासखंड में अभियान के तहत जनसहभागिता से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। रिचार्ज पिट के निर्माण एवं



हैण्डपम्प के आस-पास सफाई का कार्य भी संचालित किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गयी। साथ ही जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाई गई आगामी तीन महीने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। स्थानीयजनों को जल संरक्षण के विभिन्न तरीके भी बताए गए।

भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती उत्साह से मनाये: बृजेंद्र

पन्ना। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय में संघर्ष हुई में संपन्न हुई। उक्त आशय की जानकारी देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे ने बताया कि बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री बृजेंद्र मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे, पन्ना जिला प्रभारी श्री उमेश शुक्ला पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राम बिहारी चौरसिया प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक तिवारीमंचामी साथे। इस दौरान आगामी 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस, 6 एवं 7 अप्रैल को भाजपा के सक्रिय सदस्यों का जिला स्तरीय सम्मेलन, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संक्षेप करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा ने बताया कि आगामी 7 से 13 अप्रैल तक भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसमें बृथ स्तर पर कार्य कर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान भाजपा की केंद्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ, उनके लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में शामिल होने का आवाह किया। इसके साथ-साथ 6 अप्रैल को पन्ना जिले के समस्त बृथों में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा 3 अप्रैल को समस्त जिले में एक साथ मंडल कार्य समिति आयोजित की जाएगी। ताकि आगामी कार्यक्रमों के रूप में रेखा बृथ स्तर तक संचालित की जा सके. बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी श्री उमेश शुक्ला ने कहा कि आज हमारी पार्टी की सरकार पान पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक है विपक्ष अफवाह फैलाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है आज हमारी पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के सोपान पार कर रही है हमें पार्टी की रीति और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए।

पूर्व विधायक फुंदर चौधरी को निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए: पांडे

पन्ना। गुनौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक फुंदर चौधरी को निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष बनाए जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की गई है मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघके जिला प्रवक्ता डॉक्टर एमपी पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को एक सूत्री ज्ञापन भेज कर अनुरोध किया गया है कि प्रदेश में एक सैकड़ से अधिक आयोग मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों के पद खाली है जिनको तत्काल भर जाए तथा जो पार्टी के के लिए समर्पित ढंग से कार्य कर रहे हैं उनको तत्काल स्थान दिया जाए जिसमें आम जनता के कार्य आसानी से निपट सके ज्ञात हो की फुंदर चौधरी 1993 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं।

मादक पदार्थ के साथ 01 आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही

आरोपी के कब्जे से 02 किलो 280 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एवं 01 मोबाइल जप्त

पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्ण एस. थोटा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्रीवंदना चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी अमानगंज निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) लिये पाये जाने पर 01 आरोपी के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्ण एस. थोटा द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ (गाँजा) का परिवहन, विक्रय, उत्पादन एवं भण्डारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया

गया है। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी अमानगंज निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद रंग की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गाँजा लेकर अमानगंज से ग्राम ककरहाई तरफ जा रहा है। थाना प्रभारी अमानगंज द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना

चौहान के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी अमानगंज निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में थाना स्तर पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा बिना देरी किए तत्काल मुखबिर के बताये अनुसार ककरहाई मोड पहुँचकर देखा गया जो एक व्यक्ति सफेद बोरी लिये दिखा। उक्त व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर मौके से भागने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्पश्चात पूर्वक घेराबंदी करके पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा पूँछताछ किये जाने पर उक्त संदेही द्वारा पुलिस टीम को अपना नाम पता बताया गया। पुलिस द्वारा उक्त संदेही के

कब्जे में रखी बोरी की तलाशी लिये जाने पर उक्त बोरी में 02 पैकेट में कुल 02 किलो 280 ग्राम मादक पदार्थ (गाँजा) कीमती करीब 24 हजार रूपये का जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना अमानगंज में अपराध क्रमांक 192/25 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का कायम किया जाकर बिवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में 1. अमित उर्फ अज्जू अवस्थी पिता रामलोचन अवस्थी उम्र 33 वर्ष निवासी ककरहाई थाना अमानगंज। जप्त सामग्री में पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से 02 किलो 280 ग्राम

मादक पदार्थ गाँजा कीमती करीब 24 हजार रूपये एवं 01 मोबाइल कीमती करीब 10 हजार रूपये कुल मशरूका कीमती करीब 34 हजार रूपये का जप्त किया गया है। सराहनीय योगदान में उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अमानगंज निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री, उनि डी पी मिश्रा, प्र.आर. राजीव मिश्रा, मुकेश सोनी, मेहरबान सिंह, सतीश, विश्वास शुक्ला, द्वारका, गिरधारी, महिला स्टाफ. हेमा एवं अन्य थाना स्तर का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उक्त पुलिस टीम के कार्य को सराहना की गई है।

कलेक्टर रीवा के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबद्ध स्वेच्छक संस्थाओं एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से सामूहिक श्रमदान अभियान चलाकर स्वच्छता व जल संरक्षण का संदेश दिया गया।



नियमित सुनवाई करके एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरण निराकृत करें

सीएम हेलपलाइन में 50 दिन से अधिक की सभी शिकायतें तीन दिन में निराकृत करें : कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम तथा सीएम हेलपलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी एक वर्ष से अधिक सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका इस माह निराकरण सुनिश्चित करें। लंबित प्रकरणों में समय सीमा में प्रतिवेदन दर्ज कराएं। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित राजस्व प्रकरणों का विशेष प्रयास करके सात दिवस में निराकरण करें। सीएम हेलपलाइन में भी 50 दिन से अधिक शिकायतों का तीन दिन में निराकरण न होने पर कड़ी



अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दें। त्रैवारों के दौरान कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेलपलाइन के लंबित प्रकरणों को तहसीलदार स्वयं पढ़कर उनमें

तथ्यपरक प्रतिवेदन दर्ज करें। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण तथा प्राकृतिक आपदा में राहत राशि के प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत करें। समय सीमा के प्रकरण निराकृत न होने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्धदण्ड लगाएं। सभी एसडीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को खसरे में दर्ज

कराएं। जल संसाधन विभाग की सभी नहरों को भी खसरे में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करके खाद्यान्न का वितरण कराने के साथ-साथ 30 अप्रैल तक सभी राशन कार्डधारियों की ई केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले सेल्समैनों तथा सहायक आपूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। ई केवाईसी न कराने पर 15 अप्रैल के बाद खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा। एसडीएम 15 अप्रैल तक ई केवाईसी न कराने वाले राशन कार्डधारियों का नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना के तहत आरओआर सर्वे तथा ग्राउण्ड ट्रुथिंग का कार्य समय पर पूरा कराएं। पात्र हितग्राहियों

को भू अधिकार पत्रों का समारोहपूर्वक वितरण कराएं। सभी वक्फ सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इनका सत्यापन करके पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। प्राकृतिक आपदा में राहत राशि जारी करने के संबंध में शासन द्वारा मदवार निर्धारण कर दिया गया है। नये निर्देशों के अनुरूप राहत राशि के लंबित सभी प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी अपडेशन तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी प्राथमिकता से कराएं। पटवारियों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ई केवाईसी अपडेट कराएं। गेहूँ उर्जान के लिए पंजीकृत सभी किसानों के रकबे का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें।

प्रदेश की मूल गौवशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारु गायाँ को मिलेगा पुरस्कार

रीवा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की मूल गोवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारु गायाँ को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ राजेश मिश्रा ने बताया कि जिन पशुपालकों के पास भारतीय नस्ल की गिरि, साहीवाल, धारपारकर एवं हरियाणा आदि नस्ल की गाय हों तथा उनका दुध उत्पादन प्रति दिवस 6 लीटर से अधिक हो वह अपने पशु का पंजीयन चार अप्रैल तक विकासखण्ड स्तर अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय में करा सकते हैं। अधिकतम दुध उत्पादन वाले प्रथम 10 गौवंशों का सुवह-शाय एवं दूसरे दिन कुल तीन समय दुध क्षमता का आकलन विभाग के अधिकारियों द्वारा पशु मालिक के घर जाकर सूचीबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से प्राप्त सूची में से अधिकतम दूध उत्पादन वाले प्रथम तीन गौवंश के पशुपालकों के नाम राज्य स्तर पर प्रेषित किए जाएंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान की जिला स्तरीय समिति गठित

रीवा। जिले भर में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत आमजनता को जल संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर को बनाया गया है। समिति में सदस्य के

रूप में वन मण्डलाधिकारी, सभी एसडीएम, उप संचालक कृषि, परियोजना अधिकारी नगरीय विकास अधिकरण, सहायक संचालक उद्यानिकी, उप संचालक जनसम्पर्क, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन तथा कार्यपालन यंत्री पीएचई को शामिल किया गया है। समिति में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, प्रभारी अधिकारी पर्यावरण विभाग, प्रभारी अधिकारी संस्कृति विभाग तथा क्षेत्रीय संचालक औद्योगिक विकास निगम को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

रीवा। वर्ष 2025 में सांतवें पोषण कार्यक्रम के तहत 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जायेगा। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले में पोषण पखवाड़ा में निर्धारित थीम पर गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिये। उन्होंने जीवन के प्रथम 1000 दिवस केन्द्रित गतिविधियों, पोषण ट्रेकर में लाभार्थी माड्यूल को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार प्रसार किये जाने, सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंधन माड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन करने सहित बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिये स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु गतिविधि आयोजन के निर्देश दिये हैं।

मानस भवन में चार और पाँच अप्रैल को लगेगा पुस्तक मेला

पुस्तक मेले में 10 प्रतिशत छूट पर मिलेगी किताबें

रीवा। विद्यार्थियों को रियायती दर पर किताबें और स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए रीवा में मानस भवन में दो दिवसीय पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। पुस्तक मेला चार और पाँच अप्रैल को सबुह 10 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा। प्रत्येक दुकानदार का पंजीयन करके स्टाल संख्या आवंटित की गई है। मेले में खरीददारों और वेंडर्स के सभी समुचित व्यवस्थाएँ हैं। पुस्तक मेले में 10 प्रतिशत छूट पर किताबें मिलेंगी। पुलिस अधिकारी वाहनों

की पार्किंग तथा भीड़ प्रबंधन के लिए उचित प्रबंध करेंगे तथा आयुक्त नगर निगम मेला स्थल में पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायेंगे। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेला स्थल का निरीक्षण करके सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराएं। मेले में किताबों और स्कूल ड्रेस के सभी विक्रेता अपना स्टाल लगाएं, इसे सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी मेले के प्रत्येक काउंटर

पर कर्मचारी तैनात करें। मेले में सभी कक्षाओं की पूरी किताबों की बिक्री सुनिश्चित करें जिससे अभिभावक को किताबों के लिए पुनः दुकान न जाना पड़े। मेला स्थल में हेलपडेस्क भी स्थापित करें। इसमें प्राप्त सूचनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही से प्रतिदिन सीईओ जिला पंचायत को अवगत कराएं। फीस बढ़ाने के संबंध में यदि कोई स्कूल संचालक शासन के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

आकस्मिकता योजनान्तर्गत एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत

रीवा। जिला राहत समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ित 162 व्यक्तियों को एक करोड़ 12 लाख दस हजार 500 सौ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के 104 हितग्राहियों को 70 लाख पच्चीस हजार रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के 50 हितग्राहियों व्यक्तियों को 43 लाख 87 हजार 500 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं के सभी प्रकरण तीन दिवस में निराकृत करें

रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेलपलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन में शामिल 10 एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेलपलाइन की सभी शिकायतों का तीन दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। साथ ही मार्च माह में दर्ज शिकायतों एवं 50 दिन से अधिक शिकायतों भी सात दिवस में शत-प्रतिशत निराकरण कराएं। व्यक्तिगत रूपित लेकर स्वयं शिकायतें देखें तथा आवेदकों से बात करें। लंबित

पेयजल से जुड़ी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें : कलेक्टर



प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। शिकायतों पर तथ्यों सहित प्रतिवेदन दर्ज करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई पेयजल से जुड़ी सीएम हेलपलाइन की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। खराब हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाएँ। पंचायतों के सहयोग से

नलजल योजनाओं का भी नियमित संचालन कराएँ। जिन क्षेत्रों में जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है वहाँ हैण्डपंपों में सिंगल फेज के मोटर लगाकर पेयजल की आपूर्ति कराएँ। सीएम हेलपलाइन में दर्ज तीन हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम हैण्डपंपों में अवैध कब्जे की सभी शिकायतों का दो दिवस में निराकरण करें।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग तथा ऊर्जा विभाग में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता के सभी प्रकरणों में तीन दिवस में भुगतान कराकर संतुष्टिपूर्वक शिकायत निराकरण करें। अधीक्षण यंत्री ऊर्जा बिजली की आपूर्ति, ट्रांसफार्मर बदलने तथा बिजली बिलों में सुधार के सभी प्रकरण तीन दिवस में निराकृत कराएँ। उपार्जन को समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं।

मऊगंज जिले में पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोरेक्स का विक्रय प्रतिबंधित

रीवा। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मऊगंज जिले में पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोरेक्स कफ सिरप का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में उल्लेखनीय किया है कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कम उम्र के बच्चों एवं युवा पीढ़ी द्वारा कोरेक्स कफ सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जाता

है, जो कि सामान्य उपयोग की वस्तु होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है। कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा अज्ञानतावश कोरेक्स कफ सिरप का नशे के रूप में उपयोग किया जाना, एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रूप में परिलक्षित होते हैं। नाबालिक एवं कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं को उक्त नशे का आदी बनाया जाकर

अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त कारणों से नाबालिक बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव, सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि एवं अपराधिक गतिविधियों की संभावनाएँ हैं। कलेक्टर ने आदेश में कहा कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से मुझे यह समाधान हो गया है कि नशे के रूप में नाबालिक बच्चों / कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा

कोरेक्स कफ सिरप जैसे उत्पाद का उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण मऊगंज जिले में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ी, अब 9 अप्रैल तक होगा पंजीयन

रीवा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दिया गया है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर गेहूँ खरीदी के लिए 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेहूँ का समर्थन मूल्य 2425 रुपये तथा सरकार द्वारा घोषित 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनास के साथ किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन

होगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा जिले में गेहूँ उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्र निर्धारित कर दिए गए हैं। किसान इन खरीदी केन्द्रों में गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद की जायेगी। स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, खरीदी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र में पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं।

कार्ययोजना के अनुसार जल संरक्षण के कार्य कराएँ

जल गंगा संवर्धन अभियान से हर पंचायत में दो जल संरक्षण कार्य कराएँ : कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अभियान से जुड़े विभागों द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि में जल संरक्षण के कार्यों की पूरी कार्य योजना बनाई गई है। कार्य योजना के अनुसार जिले भर में जल संरक्षण के कार्य कराएँ। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता अभियान चलाएँ। जल गंगा संवर्धन अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के कम से कम दो कार्य अवश्य कराएँ। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने

तथा तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थल होने पर अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य कराएँ। जिले के लिए निर्धारित 18 सरोवरों के निर्माण के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराएँ। कार्य योजना में शामिल 1219 खेत तालाबों के निर्माण के लिए हितग्राहियों का चयन करके इनकी भी प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी करें।



सहित प्रतिवेदन हर सप्ताह प्रस्तुत करें। पोर्टल पर भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराएँ। कार्यपालन यंत्री पीएचई सभी हैण्डपंपों में पानी के रिचार्ज संरचना का निर्माण कराने के लिए अभियान शुरू करें। ग्राम

पंचायतों के सहयोग से सभी हैण्डपंपों में रिचार्ज संरचना का निर्माण कराएँ। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरंगा योजना से पूर्व से स्वीकृत जल संरक्षण के अधूरे कार्यों को पूरा

कराकर उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें। जनपद में जल संरक्षण के कार्यों में अन्य विभागों से समन्वय बनाकर कार्य पूरा कराएँ। आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सभी पक्के भवनों में वाटर हावैस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगवाएँ। इससे जल संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। उप संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यानिकी तथा औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी शासन के निर्देशों के अनुसार जल संरक्षण के कार्य कराएँ। सभी अधिकारी साप्ताहिक टीएल बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी दें। बैठक में जिला पंचायत के

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि सभी विकासखण्डों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुल 18208 जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें 916 हैण्डपंपों में पानी के रिचार्ज की संरचनाओं के निर्माण कार्य शामिल हैं। खेत तालाब निर्माण के लिए माडल टीएस जारी कर दिया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए भी प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। अभियान की दौरान नल जल योजनाओं की पाइपलाइन में सुधार तथा जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों की साफ-सफाई के कार्य भी कराए जा रहे हैं।